बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

# सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 225 ● नई दिल्ली ● बुधवार 24 जून 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

### राशिद हत्याकांड - पुलिस के हत्थे चढ़ा तीसरा आरोपी हारून, पैर में लगी गोली; गोलियों से गूंजा खजूरी खास

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को उत्तर-पूर्वी जिले में खजूरी खास मेट्रो स्टेशन के पास हुई मुठभेड़ के बाद हत्या के मामले में तीसरे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान 24 वर्षीय हारून सैफी के रूप में हुई है, वह भागीरथी विहार का निवासी है। मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह गिरफ्तारी उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में राशिद नामक एक युवक की हत्या के मामले में हुई है। पुलिस को मंगलवार तड़के सुबह सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उत्तर-पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ की एक टीम ने एक अभियान चलाया। इस दौरान सिग्नेचर ब्रिज और खजूरी खास मेट्रो स्टेशन के बीच के इलाके में हारून को रोका गया।

## दिल्ली में हैवानियत- 11 साल की बची को अगवा कर किया दुष्कर्म, फिर बेरहमी से ले ली जान; जंगल में मिला शव

नई दिल्ली । दिल्ली का महरौली इलाका एक दिल दहला देने वाली घटना से कांप उठा है। यहां छतरपुर एक्सटेंशनसे एक 11 वर्षीय मासूम बची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। आरोपी ने बची के शव को फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर जंगल में फेंक दिया। इस जघन्य अपराध ने पूरे इलाके में भय और आक्रोश का माहौल बना दिया है। दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के 6 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, सोमवार 22 जून की सुबह करीब पांच बजे जब बची अपने परिवार के साथ फुटपाथ पर सो रही थी, तभी आरोपी ने उसका अपहरण कर लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने बची के साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि उसने बची का शव फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर फेंक दिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि महरौली इलाके में 11 साल की बची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के आरोप में एक कैब ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी के 6 घंटे के अंदर ही कर ली गई। ड्राइवर ने सोमवार 22 जून की सुबह 5 बजे बची का अपहरण किया था, जब वह अपने परिवार के साथ फुटपाथ पर सो रही थी। आरोपी ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने बची की लाश फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर फेंक दी थी। साउथ दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया, बची अपने परिवार के साथ फुटपाथ पर सो रही थी। इसी दौरान वहां से गुजर रहे कैब चालक ने उसका फुटपाथ से अपहरण कर लिया। जिसके बाद उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और बची कई हत्या का हरियाणा में फेंक दिया। दिल्ली में अपहरण के करीब 15 मिनट बाद पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने सघन अभियान चलाया। लेकिन बची को नहीं बचाया नहीं जा सका। उन्होंने बताया, कल सुबह पुलिस ने आरोपी की कैब की पहचान की करीब 11.15 बजे उसे गिरफ्तार कर लिया। लंबी पूछताछ के बाद कल शाम आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर किया। जिसके बाद पुलिस ने हरियाणा से बची के शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए सफदरजंग अस्पताल में भेज दिया। आरोपी बिहार का रहने वाला है और दिल्ली में किराए पर रहता है। यहां एप आधारित कंपनी की कैब चलता है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

## सोशल मीडिया से हुई पहचान बनी मुसीबत, महिला ने लगाया रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप

नई दिल्ली ।

दिल्ली के बुराड़ी इलाके से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए एक शख्स पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. खुद को सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर बताने वाली एक महिला ने शिकायत दर्ज कराते हुए दावा किया है कि इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद आरोपी ने रील शूट का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया. महिला का आरोप है कि बाद में उसे ब्लैकमेल किया गया और उस पर तथा उसकी बेटी पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया. मामले में पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. महिला की शिकायत के अनुसार वर्ष 2022 में उसकी पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने अपना नाम सन्नी बताया था. आरोप है कि आरोपी ने खुद को हिंदू बताकर महिला का विश्वास हासिल किया और बाद में रील शूट करने के बहाने उसे बुराड़ी स्थित एक होटल में बुलाया. पीड़िता का दावा है कि वहीं उसके साथ दुष्कर्म किया गया.

**आपत्तिजनक सामग्री वायरल करने की धमकी**

शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि घटना के बाद आरोपी ने उसकी निजी तस्वीरों और वीडियो का हवाला देकर उसे डराया-धमकाया. पीड़िता का कहना है कि इसी दबाव का फायदा उठाकर आरोपी ने कई बार उसका यौन शोषण किया. महिला ने आरोप लगाया है कि लंबे समय तक उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा.पीड़िता के मुताबिक बाद में उसे जानकारी मिली कि जिस व्यक्ति ने खुद को सन्नी बताया था उसका वास्तविक नाम शाकिब जरदारी है और वह उत्तर प्रदेश के अमरोहा का रहने वाला है. महिला का कहना है कि इसके बाद उसने आरोपी से संपर्क समाप्त कर दिया. हालांकि शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी के भाई अफरोज और जीजा उस्मान ने भी उसे धमकाना शुरू कर दिया.

**मदरसे में बुलाकर धर्म परिवर्तन का आरोप**

महिला ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि उसे बुराड़ी स्थित एक मदरसे में बुलाया गया था. आरोप है कि वहां उस पर और उसकी बेटी पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया. शिकायत में यह भी कहा गया है कि धर्म परिवर्तन के बदले आर्थिक प्रलोभन देने की बात कही गई थी. पीड़िता का आरोप है कि जब उसने कथित दबाव का विरोध किया तो आरोपी पक्ष ने उसके पति को आपत्तिजनक सामग्री भेज दी. महिला का कहना है कि इसके बाद उसके वैवाहिक जीवन में गंभीर विवाद पैदा हो गया और परिस्थितियां ऐसी बनीं कि उसे अपना घर छोड़ना पड़ा.

**महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज**

मामले को लेकर महिला ने पहले पुलिस मुख्यालय में शिकायत दी थी. इसके बाद बुराड़ी थाने में केस दर्ज किया गया. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया है और मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है.

डीसीपी नॉर्थ राजा बांठिया ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है. फिलहाल इस केस में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

## जंतर-मंतर पर डटे सीजेपी समर्थक, बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस से विवाद; आज प्रदर्शन का चौथा दिन

जंतर मंतर

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का प्रदर्शन जंतर मंतर पर मंगलवार को चौथे दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस दौरान सीजेपी ने आरोप लगाया कि सोमवार रात प्रदर्शन स्थल पर बैरिकेडिंग की गई। प्रदर्शन स्थल को छोटा करने और उसे दो हिस्सों में बांटने की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी और गाने गाकर पुलिस की बैरीकेडिंग का विरोध जताया। वहीं पुलिस के मुताबिक, मंगलवार को किसान संगठन अमेरिका-भारत व्यापार समझौते के विरोध में प्रदर्शन करने वाले हैं।

किसी भी प्रदर्शन से पहले सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाते हैं। सीजेपी ने एसएससी और यूपीएससी अभ्यर्थियों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने बताया कि छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए अधिक लोगों का साथ जरूरी है। उन्होंने कहा की बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आएं और अपनी बात सीजेपी के मंच पर रखें। उनके अनुसार, जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से नहीं हटेंगे।

**सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके का पुलिस पर आरोप**

वहीं, धरने के तीसरे दिन प्रदर्शन स्थल पर आने वाले लोगों की पहचान संबंधी जांच को लेकर सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके और पुलिस के बीच विवाद की स्थिति देखने को मिली। दीपके ने आरोप लगाया कि धरना स्थल पर आने वाले लोगों से आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगे जा रहे हैं, जबकि वे केवल प्रदर्शन में शामिल होने, भोजन या पानी पहुंचाने जैसे कार्यों के लिए वहां पहुंच रहे हैं।

दीपके ने कहा कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा मामला है और लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि प्रदर्शनकारियों की निजी जानकारी क्यों एकत्र की जा रही है। उनके अनुसार, आधार कार्ड के माध्यम से किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच संभव है, इसलिए यह निजता से जुड़ा संवेदनशील विषय है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया।

**प्रदर्शनकारी बोले- सरकार जब तक मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाती आंदोलन जारी रहेगा**

भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के चढ़ूनी गुट ने आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की है। संगठन ने छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन में शामिल होने और अपनी मांगें भी रखने का निर्णय लिया है। इससे पहले अभिजीत दीपके ने देशभर के किसानों और मजदूरों से जंतर-मंतर पहुंचकर छात्रों के आंदोलन का समर्थन करने की अपील की थी। किसानों के समर्थन का स्वागत करते हुए दीपके ने कहा कि छात्र और किसान दोनों ही देश के भविष्य और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण वर्ग हैं। उन्होंने आंदोलन के साथ खड़े होने के लिए बीकेयू (चढ़ूनी) का आभार जताया। प्रदर्शनकारियों ने भी किसानों के इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाती, आंदोलन जारी रहेगा।

**स्वयंसेवकों ने संभाली व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी**

धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों के लिए चाय, समोसे और पानी की व्यवस्था की गई है। कई स्वयंसेवक सुबह से देर रात तक व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि ऐसे कार्यकर्ता आंदोलन की रीढ़ हैं, जो बिना किसी प्रचार-प्रसार के सेवा कार्यों में जुटे हुए हैं। वहीं, अभिजीत दीपके ने कहा कि किसी भी जन आंदोलन की वास्तविक ताकत वे लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखते हैं।

**सीजेपी ने आत्महत्या करने वाले नीट अभ्यर्थियों को दी श्रद्धांजलि**

नीट की तैयारी के दौरान आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों को सोमवार को जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने श्रद्धांजलि दी।

छात्रों, अभिभावकों और अन्य लोगों ने कैंडल जलाकर व मौन रखकर उन्हें याद किया। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपक ने परीक्षा के बढ़ते दबाव और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। वक्ताओं ने कहा कि छात्रों को केवल अंकों से नहीं, उनकी मानसिक स्थिति के आधार पर भी समझने की जरूरत है। सरकार से हेल्पलाइन, मनोवैज्ञानिक सहायता और नियमित काउंसलिंग शुरू करने की मांग की गई।

## मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, 2 चीनी नागरिकों के भारत छोड़ने पर रोक

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने वीवो मोबाइल से जुड़े करीब 20 हजार करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित दो चीनी नागरिकों को चीन जाने की अनुमति देने वाले निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि आरोपितों के फरार होने का जोखिम है और भारत व चीन के बीच प्रत्यर्पण (एक्सट्राडिशन) संधि नहीं होने के कारण उनके लौटने की कोई गारंटी नहीं है। न्यायमूर्ति तेजस करिया ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई करते हुए 17 जून 2026 के ट्रायल कोर्ट के आदेश के संचालन पर अंतरिम रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई दो जुलाई को होगी। मामले के दो आरोपितों में गुआंगवेन कुआंग उर्फ एंड्रयू और वेइगांग वांग शामिल हैं। गुआंगवेन कुआंग को अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था और नवंबर 2024 में उसे जमानत मिली थी। दोनों के खिलाफ ईडी ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपित चीन के नागरिक हैं और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता व पीएमएलए के तहत गंभीर आरोप हैं। अदालत ने माना कि चीन के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था नहीं होने के कारण यह आशंका निराधार नहीं है कि वे देश छोड़ने के बाद न लौटें अदालत ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आठ जून को गुआंगवेन कुआंग की विदेश यात्रा की अनुमति संबंधी याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन परिस्थितियों में कोई विशेष बदलाव न होने के बावजूद बाद में उसे अनुमति दे दी गई। ऐसे में ईडी की यह दलील प्रथमदृष्टया सही प्रतीत होती है कि इस स्तर पर विदेश यात्रा की अनुमति देने से जांच और न्यायिक कार्यवाही प्रभावित हो सकती है। ईडी ने अदालत को बताया कि जांच में सामने आया है कि वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी राज्य स्तरीय डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियों ने अपराध से अर्जित आय हासिल की। एजेंसी का आरोप है कि गुआंगवेन कुआंग ने लाभकारी स्वामित्व को छिपाने, कंपनियां स्थापित करने और कथित अपराध की आय को इधर-उधर करने में भूमिका निभाई। ईडी ने छह दिसंबर 2023 को पीएमएलए की धाराओं तीन, चार और 70 के तहत अभियोजन शिकायत दाखिल की थी। इसके बाद 20 दिसंबर 2023 को ट्रायल कोर्ट ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए गुआंगवेन कुआंग को आरोपित के रूप में तलब किया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने यह भी बताया कि आरोपित के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को ट्रायल कोर्ट ने 29 अप्रैल 2026 को रद कर दिया था और उस आदेश को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।

## फाइलों में अनगिनत नागरिकों की आकांक्षा-जिंदगियां- युवा आईएएस अधिकारियों से पीएम मोदी का संवाद, दिया गुरुमंत्र

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2024 बैच के 183 आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की। ये सभी अधिकारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में तैनात हैं। इस दौरान युवा अधिकारियों ने अपने फील्ड प्रशिक्षण और मंत्रालयों के कामकाज के अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि दो साल के जमीनी अनुभव के बाद वे अब एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, जहां उनके फैसले करोड़ों नागरिकों का भविष्य तय करेंगे। उन्होंने जोर दिया कि लोक सेवा की असली परीक्षा ईमानदारी, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ वास्तविक स्थितियों को संभालने में है। प्रधानमंत्री ने युवा सिविल सेवकों से राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित रहने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिक देवो भव का मंत्र देते हुए कहा कि हर प्रशासनिक फाइल के पीछे एक इंसान की उम्मीदें, चिंताएं और जीवन छिपा होता है। अधिकारियों को हर फैसला लेते समय नागरिकों को केंद्र में रखना चाहिए। उन्होंने शासन

को अधिक संवेदनशील, जवाबदेह और समावेशी बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने होल-ऑफ-गवर्नमेंट यानी पूरे सरकारी तंत्र के एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि बड़ी विकास चुनौतियों को अलग-अलग रहकर हल नहीं किया जा सकता। विभागों के बीच बेहतर तालमेल ही सार्थक और स्थायी परिणाम ला सकता है।

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक फैसला देश के विकास में योगदान देने वाला होना चाहिए। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग, ऊर्जा सुरक्षा और युवाओं के लिए अवसर पैदा करने को आज की प्राथमिकता बताया। पिछले दशक में आए बदलावों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अब प्रशासन प्रक्रिया के बजाय परिणामों पर ध्यान देता है। उन्होंने डिजिटल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।

उन्होंने कहा कि तकनीक से सेवाओं में पारदर्शिता आई है और नागरिकों का काम आसान हुआ है। डेटा-आधारित शासन पर बात करते हुए पीएम ने कहा कि डेटा सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि यह लाखों लोगों की चुनौतियों और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे नियमित रूप से जांचें कि क्या नीतियां जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने इस बैच में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना की। उन्होंने बताया कि इस बैच में 40 प्रतिशत से अधिक महिला अधिकारी हैं।

अंत में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने पद से नहीं, बल्कि अपने काम से मिलने वाले परिणामों से संतुष्ट हों। उन्हें पूरा भरोसा है कि इन युवाओं की ऊर्जा भारत की विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।

**सम्पादकीय...**

## बदलती रणनीतिक तस्वीर

पश्चिम एशिया में हाल के महीनों में हुए संघर्ष और कूटनीतिक घटनाक्रमों के बीच ईरान ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। ईरान के मुख्य वार्ताकार और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरूमध्य ईरान के प्रशासनिक नियंत्रण में ही रहेगा और इसे युद्ध-पूर्व स्थिति में वापस नहीं लौटाया जाएगा। उनका यह बयान केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया की बदलती शक्ति-संरचना और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के समुद्री मार्ग से होने वाले तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, इराक और ईरान जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों का अधिकांश निर्यात इसी रास्ते से दुनिया के विभिन्न देशों तक पहुंचता है। इसलिए इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का तनाव या राजनीतिक बदलाव वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। हाल ही में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़े तनाव ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया था। संघर्ष के दौरान समुद्री व्यापार प्रभावित हुआ, तेल टैंकरों की आवाजाही धीमी हुई और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ गई। हालांकि बाद में कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश हुई, लेकिन ईरान का ताजा बयान दर्शाता है कि वह युद्ध के बाद की व्यवस्था को अपने रणनीतिक हितों के अनुसार आकार देना चाहता है। मोहम्मद बाकिर गालिबाफ का यह कहना कि होर्मुज जलडमरूमध्य युद्ध-पूर्व स्थिति में नहीं लौटेगा, कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। पहला, यह दर्शाता है कि ईरान स्वयं को इस संघर्ष के बाद अधिक प्रभावशाली स्थिति में देख रहा है। दूसरा, यह संदेश अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए है कि क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल चुका है। तीसरा, यह संकेत भी है कि ईरान भविष्य में इस समुद्री मार्ग पर अपनी भूमिका और प्रभाव को और मजबूत करना चाहता है। ईरान लंबे समय से होर्मुज जलडमरूमध्य को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानता रहा है। अतीत में जब भी उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए या अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ा, तब उसने कई बार इस मार्ग के महत्व का उल्लेख करते हुए अपनी सामरिक क्षमता का प्रदर्शन किया। हालांकि उसने कभी भी लंबे समय तक जलडमरूमध्य को बंद नहीं किया, क्योंकि इससे वैश्विक बाजार के साथ-साथ ईरान की अपनी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंच सकता था। गालिबाफ का बयान यह भी दर्शाता है कि ईरान युद्ध और उसके बाद हुई वार्ताओं को अपनी कूटनीतिक सफलता के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। किसी भी संघर्ष के बाद विजेता केवल सैन्य उपलब्धियों से नहीं, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक प्रभाव से भी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करते हैं। ईरान का वर्तमान रुख इसी प्रक्रिया का हिस्सा माना जा सकता है। भारत के लिए भी यह घटनाक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से पूरा करता है। पश्चिम एशिया भारत का प्रमुख ऊर्जा साझेदार है। ऐसे में होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा और स्थिरता सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी हुई है। हाल ही में भारतीय ध्वज वाले तेल टैंकर देश वैभव, देश विभोर और सम्मान हेराल्ड का सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य पार करना भारत के लिए राहत की खबर थी। इन जहाजों के माध्यम से लाखों टन कच्चा तेल भारत पहुंच रहा है। लेकिन ईरान के ताजा बयान से स्पष्ट है कि क्षेत्र में सामान्य स्थिति पूरी तरह बहाल नहीं हुई है और भविष्य में भी भू-राजनीतिक चुनौतियां बनी रह सकती हैं। वैश्विक ऊर्जा बाजार भी इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए हैं। तेल की कीमतें केवल वास्तविक आपूर्ति पर निर्भर नहीं करतीं, बल्कि संभावित जोखिमों और राजनीतिक अनिश्चितताओं से भी प्रभावित होती हैं। यदि निवेशकों को यह लगता है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ सकता है, तो तेल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। इसका असर दुनिया भर में महंगाई, परिवहन लागत और औद्योगिक उत्पादन पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का यह बयान केवल बाहरी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि घरेलू राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। संघर्ष और आर्थिक चुनौतियों के बीच ईरानी नेतृत्व अपने नागरिकों को यह संदेश देना चाहता है कि देश ने अंतरराष्ट्रीय दबावों के बावजूद अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत बनाए रखा है। इस प्रकार यह बयान राष्ट्रीय गौरव और राजनीतिक समर्थन जुटाने का माध्यम भी बन सकता है। दूसरी ओर, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। यदि वे ईरान के इस रुख को स्वीकार करते हुए कूटनीतिक संवाद जारी रखते हैं, तो क्षेत्र में स्थिरता बनी रह सकती है। लेकिन यदि किसी प्रकार का नया टकराव उत्पन्न होता है, तो इसका असर पूरे विश्व पर पड़ सकता है। होर्मुज जलडमरूमध्य केवल एक समुद्री मार्ग नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था का केंद्रीय बिंदु है। पश्चिम एशिया का इतिहास बताता है कि यहां की राजनीति अक्सर वैश्विक राजनीति को प्रभावित करती है। तेल संसाधनों, सामरिक समुद्री मार्गों और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विताओं के कारण यह क्षेत्र हमेशा अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। आज भी स्थिति अलग नहीं है। ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के हित इस क्षेत्र में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। अंततः, मोहम्मद बाकिर गालिबाफ का बयान पश्चिम एशिया में बदलते शक्ति समीकरणों का संकेत है। यह दर्शाता है कि ईरान संघर्ष के बाद स्वयं को अधिक मजबूत स्थिति में देख रहा है और वह क्षेत्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करना चाहता है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह रुख स्थायी शांति और नई व्यवस्था की ओर ले जाता है या फिर क्षेत्र में किसी नए तनाव की भूमिका तैयार करता है। होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण और प्रभाव का प्रश्न केवल ईरान या पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं है। यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए दुनिया की निगाहें अब इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं, जहां लिए गए निर्णय आने वाले वर्षों की वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर सकते हैं।

# तनाव के बीच उम्मीद

अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के अंतिम परिणाम को लेकर अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच हुई पहले दौर की बातचीत में भी तनातनी बनी रही। अमेरिका प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जे.डी. वेंस, विशेषदूत स्टीव विटकॉफ और वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर ने किया। जबकि ईरान की तरफ से प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री अब्बास अराघची और संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद गालिबाफ ने किया। यद्यपि 80 मिनट की वार्ता के बाद ईरान प्रतिनिधिमंडल बैठक से बाहर आ गया और उसने शांति समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। तनाव के बावजूद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प व्यापक क्षेत्रीय युद्ध विराम हासिल करने के लिए तेहरान के साथ राजनयिक संबंध फिर से शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जेडी वेंस ने वार्ता को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि हमारे सामने सवाल यह है कि हम मिलकर और कितना कुछ हासिल कर सकते हैं क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं क्या हम मध्य पूर्व में संबंधों को स्थायी रूप से बदल सकते हैं या फिर हम पुराने तरीके पर लौट जाएंगे, जो हमारी पसंद नहीं है लेकिन निश्चित रूप से ऐसा होने की पूरी संभावना है।वेंस ने कहा कि ट्रम्प ने अमेरिकी टीम को ईरान के साथ संबंधों में मौलिक बदलाव लाने का निर्देश दिया था, यदि तेहरान उन गतिविधियों को छोड़ने की इच्छा दिखाता है जिन्हें वाशिंगटन अस्थिरता पैदा करने वाला मानता है। वेंस ने कहा, राष्ट्रपति ट्रम्प ने हमसे जो करने को कहा है, वह ईरान के लोगों के साथ हमारे संबंधों को बदलने के लिए एक नई शुरुआत करना है। यदि ईरान का नेतृत्व क्षेत्रीय अस्थिरता का कारक बनने से पीछे हटने को तैयार है, यदि वे दीर्घकालिक रूप से परमाणु हथियार बनाने की महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने को तैयार हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका उस देश के साथ अपने संबंधों को मौलिक रूप से बदलने को तैयार है। लेकिन असली मुद्दा लेबनान में इजराइली हमलों का रहा। यद्यपि डोनाल्ड ट्रम्प ने इजराइल को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्हें लेबनान और हिजबुल्लाह के मामले

> **जेडी वेंस ने वार्ता को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि हमारे सामने सवाल यह है कि हम मिलकर और कितना कुछ हासिल कर सकते हैं क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं क्या हम मध्य पूर्व में संबंधों को स्थायी रूप से बदल सकते हैं या फिर हम पुराने तरीके पर लौट जाएंगे, जो हमारी पसंद नहीं है लेकिन निश्चित रूप से ऐसा होने की पूरी संभावना है।**

में जिम्मेदारी दिखाने को कहा है। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाता जा रहा है। जिसकी वजह से रोज लोग मर रहे हैं लेकिन नेतन्याहू शांति समझौते के विरुद्ध सख्त रवैया अपनाए हुएहैं। ईरान कई सालों से हिजबुल्लाह का पालन पोषण कर रहा है और इजराइल के विरुद्ध प्रॉक्सी युद्ध में उसका इस्तेमाल कर रहा है। यद्यपि जेडी वेंस सुलह का रुख अपनाए हुएहैं लेकिन ट्रम्प वार्ता के दौरान भी तेहरान को कड़ी चेतावनियां देने से बाज नहीं आ रहे। ट्रम्प दबाव की रणनीति अपना रहे हैं और लगातार धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर लगाम नहीं लगाई तो फिर अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा प्रहार करेगा। इसी बीच ट्रम्प ने एक नया राग छेड़ दिया है।

ट्रम्प लेबनान और हिजबुल्लाह से जुड़े मामलों में सीरिया को जिम्मेदारी सौंपने की बात कह रहे हैं। ट्रम्प का मानना है कि सीरियाई सरकार लेबनान में ईरान समर्थित आतंकी समूह हिजबुल्लाह की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ी भूमिका निभा सकता है जबकि सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल लेबनान के मामलों में अपने हाथ नहीं जलाना चाहते। उनका कहना है कि वे लेबनान में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे लेकिन वे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रयासों का समर्थन करते हैं। सवाल यह भी है कि क्या इजराइल सीरिया की भूमिका को स्वीकार करेगा। स्विट्जरलैंड में टकराव के बावजूद बातचीत की निगरानी के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन भी किया गया। दोनों पक्षों ने लेबनान में सैन्य अभियानों को समाप्त करने के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य पर एक संचार लाइन और एक संघर्ष निवारण सैल की स्थापना की। इसी बीच अमेरिका ने ईरानी तेल निर्यात पर लगे कुछ प्रतिबंधों को हटा दिया है और कुछ जब्त सम्पत्तियों को भी जारी कर दिया है। बातचीत में मध्यस्थ कतर का कहना है कि वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है क्योंकि दोनों पक्षों ने 60 दिवसीय रोड मैप पर सहमति जताई है। जेडी वेंस शांति समझौते को लेकर सकारात्मक रुख इसलिए अपनाए हुए हैं क्योंकि उनका राजनीतिक भविष्य इसी समझौते पर टिका हुआ है। जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के चुनावों में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रम्प के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रम्प इसका पूरा दोषवेंस पर डाल देंगे। अमेरिका में भी समीकरणतेजी से बदल रहे हैं। जेडी वेंस के लिए शांति समझौता उनके राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। हालांकि मार्को रूबियो भी राष्ट्रपति पद के लिएसंभावित दावेदार हैं लेकिन ज्यादातर सर्वेक्षणों में वेंस को बढ़त दिखाई दे रही है।

अमेरिका और खाड़ी देश जल्द से जल्द होर्मुज को खुलवाना चाहते हैं क्योंकि ऐसा न होने की स्थिति में तेल और ऊर्जा का संकट बढ़जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात तो होर्मुज पर निर्भरता कम करने की रणनीति पर काम कर रहा है। भारत के लिएभी होर्मुज संकट एक बड़ा सबक है। भारत के लिएआपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाना वैकल्पिक समुद्री एवं जमीनी गलियारों में निवेश करना और रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए। तनातनी में खत्म हुई शांति वार्ता में प्रगति तो हुई है लेकिन रास्ते अभी भी जटिल हैं। बेहतर यही होगा कि अमेरिका-ईरान संयम से काम लेते हुए नई शुरुआत करें और पूरी दुनिया को राहत प्रदान करें।

## जापान ने बढ़ाई वीज़ा फीस

जापान सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए वीज़ा शुल्क में अभूतपूर्व वृद्धि की घोषणा की है। यह फैसला न केवल अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक पर्यटन, शिक्षा और श्रम प्रवासन के क्षेत्र में भी व्यापक प्रभाव डाल सकता है। नई व्यवस्था के तहत जापान में प्रवेश के लिए एकल-प्रवेश (सिंगल एंट्री) वीज़ा की फीस 3,000 येन से बढ़ाकर 15,000 येन कर दी गई है, जबकि बहु-प्रवेश (मल्टीपल एंट्री) वीज़ा की फीस 6,000 येन से बढ़ाकर 30,000 येन कर दी गई है। यह वृद्धि लगभग 500 प्रतिशत की है और पिछले 48 वर्षों में पहली बार जापान ने अपने वीज़ा शुल्क में बदलाव किया है। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने इस निर्णय का बचाव करते हुए कहा कि यह कदम मुद्रास्फीति (महंगाई) और वर्तमान विनिमय दरों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। उनका तर्क है कि पिछले कई दशकों में प्रशासनिक लागत बढ़ी है और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप शुल्क संरचना में संशोधन आवश्यक हो गया था। हालांकि इस तर्क को लेकर बहस भी शुरू हो गई है। आलोचकों का कहना है कि महंगाई का असर प्रशासनिक खर्चों पर पड़ना स्वाभाविक है, लेकिन जापानी मुद्रा येन की कमजोरी को वीज़ा शुल्क बढ़ाने का आधार बनाना पूरी तरह तर्कसंगत नहीं लगता। वीज़ा आवेदन की प्रक्रिया मुख्य रूप से जापान के सरकारी तंत्र के भीतर ही संचालित होती है और इसमें विदेशी श्रम या आयातित संसाधनों की बड़ी भूमिका नहीं होती। ऐसे में कई विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार बढ़ती पर्यटक संख्या से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने का भी प्रयास कर रही है। जापान पिछले कुछ वर्षों से रिकॉर्ड संख्या में विदेशी पर्यटकों का स्वागत कर रहा है। कोविड-19 महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र में तेज़ी से सुधार हुआ है और कमजोर येन के कारण जापान विदेशी पर्यटकों के लिए अपेक्षाकृत सस्ता गंतव्य बन गया है। अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई देशों के नागरिकों के लिए जापान की यात्रा पहले की तुलना में अधिक आकर्षक हो गई है। ऐसे समय में वीज़ा शुल्क बढ़ाना सरकार के लिए अतिरिक्त आय का एक साधन भी बन सकता है। जापानी सरकार का दावा है कि इस निर्णय से विदेशी पर्यटकों की संख्या पर तत्काल कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। सरकार का अनुमान है कि नए शुल्क ढांचे से वर्ष 2026 में लगभग 116 अरब येन से अधिक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता है। यह राशि जापान के पर्यटन और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने में उपयोग की जा सकती है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह शुल्क वृद्धि सभी विदेशी नागरिकों को समान रूप से प्रभावित नहीं करेगी। जापान कई देशों के नागरिकों को अल्पकालिक पर्यटन के लिए वीज़ा-मुक्त प्रवेश की सुविधा देता है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और अधिकांश यूरोपीय संघ के देशों के नागरिकों को पर्यटन उद्देश्य से 90 दिनों तक बिना वीज़ा जापान में प्रवेश करने की अनुमति है। इसलिए इन देशों के अधिकांश पर्यटक सीधे तौर पर इस शुल्क वृद्धि से प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन यदि वे अध्ययन, रोजगार, शोध या अन्य गैर-पर्यटन उद्देश्यों से जापान जाना चाहते हैं, तो उन्हें वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा और नई दरों के अनुसार शुल्क देना पड़ेगा। सबसे अधिक प्रभाव उन देशों के नागरिकों पर पड़ सकता है जिन्हें जापान में प्रवेश के लिए पहले से वीज़ा प्राप्त करना अनिवार्य है। इनमें चीन, रूस तथा मध्य पूर्व और अफ्रीका के कई देश शामिल हैं।

# एंडी बर्नहैम- क्या ब्रिटेन को मिलने वाला है नया प्रधानमंत्री

ब्रिटेन की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर द्वारा प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा के बाद देश में नए नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच सबसे प्रमुख नाम एंडी बर्नहैम का सामने आ रहा है। यदि लेबर पार्टी सत्ता में बनी रहती है और बर्नहैम पार्टी नेतृत्व हासिल करने में सफल होते हैं, तो वह ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एंडी बर्नहैम का राजनीतिक सफर संघर्ष, अनुभव और जनसरोकारों से जुड़ा रहा है। उन्हें लंबे समय से लेबर पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। ब्रिटिश राजनीति में उनकी पहचान एक ऐसे नेता की है जो आम लोगों के मुद्दों को मजबूती से उठाते हैं और क्षेत्रीय असमानताओं के खिलाफ खुलकर आवाज उठाते हैं। एंडी बर्नहैम का जन्म जनवरी 1970 में इंग्लैंड के लिवरपूल शहर में हुआ था। उनका पालन-पोषण उत्तर-पश्चिमी इंग्लैंड में हुआ। किशोरावस्था से ही उनकी रुचि राजनीति में थी और मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने लेबर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। यह वही समय था जब ब्रिटेन में सामाजिक और आर्थिक बदलावों को लेकर व्यापक बहस चल रही थी।

शिक्षा के क्षेत्र में भी बर्नहैम का रिकॉर्ड प्रभावशाली रहा है। उन्होंने प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई की। विश्वविद्यालय से निकलने के बाद उन्होंने राजनीति को अपना करियर बनाया और धीरे-धीरे पार्टी संगठन में अपनी पहचान स्थापित की। साल 2001 में एंडी बर्नहैम पहली बार संसद सदस्य चुने गए। इसके बाद उन्होंने तत्कालीन लेबर सरकारों में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं। पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और गॉर्डन ब्राउन की सरकारों में उन्होंने गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उनकी प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए उन्हें 2008 में संस्कृति सचिव बनाया गया। इसके एक वर्ष बाद 2009 में उन्हें स्वास्थ्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस पद पर रहते हुए वह इंग्लैंड की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा यानी एनएचएस के प्रमुख राजनीतिक संरक्षक बने। स्वास्थ्य सेवा ब्रिटेन की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थाओं में से एक मानी जाती है और इस पद ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई।

हालांकि बर्नहैम की महत्वाकांक्षा केवल मंत्री बनने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने दो बार लेबर पार्टी का नेता बनने की कोशिश की। पहली बार 2010 में उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन एड मिलिबैंड से हार गए। इसके बाद 2015 में उन्होंने फिर नेतृत्व की दौड़ में हिस्सा लिया, लेकिन इस बार जेरेमी कॉर्बिन ने उन्हें पराजित कर दिया। इन असफलताओं के बावजूद उन्होंने राजनीति से दूरी नहीं बनाई। बल्कि उन्होंने अपनी ऊर्जा स्थानीय शासन और क्षेत्रीय विकास की दिशा में लगाई। वर्ष 2017 में उन्होंने संसद छोड़ दी और ग्रेटर मैनचेस्टर के पहले प्रत्यक्ष निर्वाचित मेयर बने। मेयर के रूप में उनका कार्यकाल उनकी राजनीतिक छवि को नई ऊंचाई देने वाला साबित हुआ। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, आवास, रोजगार और क्षेत्रीय विकास जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया। उनका मानना था कि लंदन और दक्षिणी इंग्लैंड की तुलना में उत्तरी क्षेत्रों को कम अवसर और संसाधन मिलते हैं। इसलिए उन्होंने नॉर्दर्न इंग्लैंड की आवाज बनने का प्रयास किया। कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी लोकप्रियता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जब ब्रिटिश सरकार और स्थानीय प्रशासन के बीच आर्थिक सहायता को लेकर विवाद हुआ, तब बर्नहैम ने खुलकर केंद्र सरकार को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि उत्तरी इंग्लैंड के लोगों को पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। उनकी इसी आक्रामक और प्रभावशाली भूमिका के कारण मीडिया ने उन्हें किंग ऑफ द नॉर्थ यानी उत्तर का राजा कहना शुरू कर दिया। यह उपनाम लोकप्रिय टेलीविजन श्रृंखला गेम ऑफ थ्रोन्स से प्रेरित था। हालांकि यह केवल एक मीडिया उपाधि थी, लेकिन इससे उनकी लोकप्रियता और राजनीतिक प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। साल 2026 में एंडी बर्नहैम ने राष्ट्रीय राजनीति में वापसी की। उन्होंने मेकरफील्ड संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़कर संसद में वापसी की। इस चुनाव में उनकी जीत बेहद प्रभावशाली रही। सुधार यूके पार्टी उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी के रूप में सामने आई, लेकिन वह 9,000 से अधिक मतों के अंतर से पीछे रह गई। इस जीत का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि 2024 के आम चुनाव में लेबर पार्टी को इस क्षेत्र में लगभग 45 प्रतिशत मत मिले थे। बर्नहैम की उम्मीदवारी के बाद यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 55 प्रतिशत तक पहुंच गया। इससे यह संकेत मिलता है कि वह केवल पार्टी के नेता ही नहीं, बल्कि मतदाताओं को आकर्षित करने वाले लोकप्रिय जननेता भी हैं। आज जब कीर स्टारमर के इस्तीफे के बाद नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा हो रही है, तब एंडी बर्नहैम को सबसे मजबूत दावेदारों में माना जा रहा है। उनके पास प्रशासनिक अनुभव, संसदीय समझ, संगठनात्मक क्षमता और जनाधार–चारों मौजूद हैं। हालांकि उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। ब्रिटेन वर्तमान में आर्थिक दबाव, सार्वजनिक सेवाओं की समस्याओं, आव्रजन संकट और राजनीतिक ध्रुवीकरण जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। यदि बर्नहैम नेतृत्व संभालते हैं, तो उन्हें केवल पार्टी को एकजुट रखना ही नहीं होगा, बल्कि जनता को यह विश्वास भी दिलाना होगा कि लेबर पार्टी देश को स्थिर और समृद्ध भविष्य दे सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बर्नहैम की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्थानीय से राष्ट्रीय राजनीति की शैली है। वह केवल बड़े वैचारिक भाषणों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि परिवहन, स्वास्थ्य, रोजगार और जीवन-स्तर जैसे मुद्दों को सीधे जनता से जोड़ते हैं। अंततः, एंडी बर्नहैम की कहानी धैर्य, राजनीतिक प्रतिबद्धता और लगातार संघर्ष की कहानी है। दो बार नेतृत्व चुनाव हारने के बावजूद उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा जारी रखी और स्थानीय शासन के माध्यम से खुद को एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया। आज जब ब्रिटेन नए नेतृत्व की तलाश में है, तब बर्नहैम एक ऐसे नेता के रूप में उभर रहे हैं जो देश की राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं।आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि क्या एंडी बर्नहैम वास्तव में लेबर पार्टी का नेतृत्व संभालकर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं। लेकिन इतना निश्चित है कि वर्तमान समय में वह ब्रिटिश राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली चेहरों में से एक बन चुके हैं।

# आस्था, जवाबदेही और पारदर्शिता की अग्निपरीक्षा -समग्र व्यापक विश्लेषण

वैश्विक स्तरपर दुनियाँ के सबसे बड़े आध्यात्मिक स्थलों में गिने जाने वाले तीर्थ, मंदिर,मठ, गुरुद्वारे,मस्जिदें और चर्च केवल आस्था के केंद्र ही नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले दान और चढ़ावे के कारण विशाल आर्थिक संस्थान भी बन चुके हैं। ऐसे में यदि कहीं दान राशि, चढ़ावे या ट्रस्ट निधियों के उपयोग को लेकर वित्तीय अनियमितताओं, पारदर्शिता की कमी अथवा जवाबदेही पर प्रश्न उठते हैं,तो उससे केवल धन का नुकसान नहीं होता, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं और विश्वास को भी गहरी ठेस पहुंचती है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि यही कारण है कि अब समय की मांग है कि सभी आध्यात्मिक एवं धार्मिक संस्थानों के लिए आय-व्यय का नियमित सार्वजनिक लेखा-जोखा, स्वतंत्र ऑडिट, डिजिटल भुगतान व्यवस्था वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट का प्रकाशन तथा प्रचलित कानूनों, नियमों और विनियमों का कठोर अनुपालन अनिवार्य बनाया जाए। आस्था और प्रशासन का संतुलन तभी संभव है जब श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए प्रत्येक रुपये के उपयोग में पूर्ण पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और ईमानदारी दिखाई दे। वित्तीय शुचिता केवल कानूनी आवश्यकता नहीं, बल्कि धर्मस्थलों की नैतिक प्रतिष्ठा और समाज के विश्वास को बनाए रखने की सबसे बड़ी कसौटी भी है। साथियों अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं,बल्कि करोड़ों भारतीयों और विश्वभर के रामभक्तों की सदियों पुरानी आस्था,संघर्ष और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। ऐसे में मंदिर में चढ़ावे,दान राशि, सोना-चांदी तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के कथित गबन,वित्तीय अनियमितताओं,शिलाओं के गायब होने, कर्मचारियों की संलिप्तता के आरोपों तथा जांच एजेंसियों की सक्रियता से जुड़ी खबरों ने पूरे देश में व्यापक चर्चा और चिंता पैदा कर दी है। यह मामला केवल धन के कथित दुरुपयोग का नहीं, बल्कि उस विश्वास की परीक्षा का है जो करोड़ों श्रद्धालुओं ने मंदिर व्यवस्था पर रखा है। सोमवार 22 जून 2026 की शाम 6 बजे तक उपलब्ध घटनाक्रमों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी जांच निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है, उच्च न्यायालय में जनहित याचिका पर सुनवाई हो चुकी है, और मंदिर ट्रस्ट ने दान प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सख्त एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि अंतिम सत्य अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है, इसलिए किसी भी व्यक्ति या संस्था को दोषी मानना अभी उचित नहीं होगा। साथियों, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि विवाद की शुरुआत उन आरोपों से हुई जिनमें मंदिर के चढ़ावे और दान प्रबंधन में कथित अनियमितताओं की बात कही गई। आरोपों में नकदी, सोना- चांदी और अन्य चढ़ावे के लेखा- जोखा पर प्रश्न उठाए गए। इसके बाद मामला राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक स्तरपर चर्चा का विषय बन गया। बढ़ते विवाद के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया।एसआईटी में वरिष्ठ प्रशासनिक, पुलिस और वित्तीय अधिकारियों को शामिल किया गया तथा उसे सीमित समय में प्रारंभिक एवं अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दायित्व दिया गया।जांच के दौरान अनेक दावे सामने आए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एसआईटी ने धन के प्रवाह (मनी ट्रेल), दान पेटियों की निगरानी व्यवस्था, कर्मचारियों की भूमिका, रिकॉर्ड मिलान और डिजिटल साक्ष्यों की जांच पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। जांचकर्ताओं ने उन लोगों से पूछताछ की जिनके नाम प्रारंभिक आरोपों में सामने आए थे। एसआईटी का उद्देश्य यह पता लगाना था कि यदि कोई वित्तीय गड़बड़ी हुई है तो वह किस स्तर पर हुई, धन कहां गया, किन खातों में गया और उसकी अंतिम जिम्मेदारी किसकी बनती है। साथियों, 22 जून 2026 तक सामने आई रिपोर्टों के अनुसार एसआईटी जांच अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। कुछ मीडिया स्रोतों में दावा किया गया कि जांच टीम ने अनेक दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए है तथा कुछ निगरानी संबंधी कमियों और प्रशासनिक खामियों की पहचान की है। कुछ रिपोर्टों में सीसीटीवी फुटेज के अभाव या कथित छेड़छाड़ तथा निगरानी व्यवस्था की कमजोरी का उल्लेख किया गया है। हालांकि इन दावों की अंतिम पुष्टि केवल आधिकारिक रिपोर्ट या न्यायिक प्रक्रिया से ही होगी।एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट को लेकर जो सूचनाएं विभिन्न माध्यमों से सामने आई हैं, उनके अनुसार जांच दल ने दान प्रबंधन प्रणाली में कई संरचनात्मक कमजोरियों की ओर संकेत किया है। रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि कुछ महत्वपूर्ण अवधि की निगरानी सामग्री उपलब्ध नहीं थी तथा प्रशासनिक जवाबदेही की श्रृंखला को और मजबूत करने की आवश्यकता है। कथित रूप से जांच दल ने व्यापक प्रशासनिक सुधारों, बेहतर निगरानी व्यवस्था और वित्तीय नियंत्रण को सुदृढ़ करने की सिफारिशें भी की हैं। हालांकि एसआईटी की अंतिम और आधिकारिक रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से जारी होने के बाद ही इन निष्कर्षों की प्रामाणिक स्थिति स्पष्ट होगी। साथियों, इस पूरे विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि स्वयं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आरोपों को गंभीरता से लिया और जांच का समर्थन किया। ट्रस्ट ने पहले भी कहा था कि नियमित ऑडिट और वित्तीय समीक्षा में कोई बड़ी गड़बड़ी सामने नहीं आई है, फिर भी यदि किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ट्रस्ट का कहना रहा है कि पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है।कथित दान अनियमितताओं के बाद ट्रस्ट द्वारा दान प्रबंधन प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार दान पेटियों की निगरानी, डिजिटल रिकॉर्डिंग, लेखांकन प्रक्रिया, बहुस्तरीय सत्यापन, सुरक्षा प्रोटोकॉल तथा वित्तीय ऑडिट प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की शंका या विवाद की गुंजाइश न्यूनतम रहे और श्रद्धालुओं का विश्वास अक्षुण्ण बना रहे। साथियों, इस प्रकरण में न्यायिक पहलू भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से ऑडिट कराने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में दाखिल की गई। याचिकाकर्ता ने स्वतंत्र जांच, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की थी।यह मामला 18 जून 2026 को अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुआ था। समयाभाव के कारण उस दिन विस्तृत सुनवाई नहीं हो सकी और मामले को 22 जून 2026 के लिए सूचीबद्ध किया गया था।22 जून की सुनवाई का प्रमुख केंद्र यह था कि क्या मामले में स्वतंत्र जांच एजेंसी, विशेष रूप से सीबीआई जांच अथवा कैग ऑडिट की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में अधिकतम पारदर्शिता आवश्यक है। दूसरी ओर राज्य सरकार और संबंधित पक्षों का रुख यह रहा कि एसआईटी जांच पहले से जारी है और उसके निष्कर्ष सामने आने दिए जाने चाहिए। अंतिम न्यायिक निर्देशों और आदेशों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह मामला केवल वित्तीय नहीं बल्कि सार्वजनिक विश्वास से भी सटीकता से जुड़ा हुआ है।साथियों, राजनीतिक स्तरपर भी इस प्रकरण ने तीखी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की हैं। विपक्षी दलों ने स्वतंत्र जांच की मांग उठाई, जबकि सरकार और ट्रस्ट से जुड़े पक्षों ने कहा कि जांच पूरी होने से पहले निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सार्वजनिक रूप से कहा कि सत्य सामने आएगा और लोगों को जांच पूरी होने तक धैर्य रखना चाहिए।इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू यह है कि इसे किसी राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय संस्थागत जवाबदेही के दृष्टिकोण से देखा जाए। यदि किसी स्तर पर भ्रष्टाचार या गबन सिद्ध होता है तो दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैण्डवनगर एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/...)

# एसडीएम के निर्देश पर खुला सार्वजनिक रास्ता, ग्रामीणों ने चंदा जुटा लगाई जेसीबी मशीन

**- मठिया में सड़क व चकरोड अतिक्रमण मुक्त, वर्षों पुरानी समस्या खत्म**

कुशीनगर। तमकुहीराज तहसील क्षेत्र के मठिया गांव में पिच सड़क व चकरोड पर किए गए अतिक्रमण को मंगलवार को हटा दिया गया। उपजिलाधिकारी आकांक्षा मिश्रा के निर्देश पर हुई कार्रवाई व ग्रामीणों की पहल से सार्वजनिक मार्ग पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त हो गया, जिससे लोगों को राहत मिली। गांव निवासी एक युवक ने उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी कि कुछ लोगों ने सड़क व चकरोड पर मिट्टी, ईंट व मलबा रखकर रास्ता बाधित कर दिया है। शिकायत के बाद एसडीएम ने हल्का लेखपाल अविनाश गुप्ता को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जांच के दौरान लेखपाल ने मौके का निरीक्षण कर संबंधित लोगों को तीन दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। समय सीमा समाप्त होने पर ग्रामीणों ने आपस में चंदा एकत्र कर जेसीबी मशीन मंगवाई और रास्ते से मिट्टी व मलबा हटवाना शुरू कराया।? कार्रवाई के दौरान संबंधित लोगों ने भी सहयोग किया, जिससे कुछ ही घंटों में सड़क व चकरोड पूरी तरह साफ हो गए। इसके बाद किसानों, छात्रों व ग्रामीणों का आवागमन सामान्य हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि रास्ता बाधित होने से लंबे समय से परेशानी हो रही थी। उन्होंने उपजिलाधिकारी आकांक्षा मिश्रा व लेखपाल अविनाश गुप्ता के प्रयासों की सराहना करते हुए सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने का संकल्प लिया।

## सीनियर तैराकी प्रतियोगिता के लिए 25 जून को जिला स्तरीय ट्रायल

कुशीनगर। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देश पर प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर महिला एवं पुरुष तैराकी प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों के चयन हेतु जिला एवं मंडलीय स्तर पर ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी उप क्रीड़ा अधिकारी प्रवेश कुमार रावत ने दी। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय चयन ट्रायल 25 जून 2026 को प्रातः 10 बजे से स्पोर्ट्स स्टेडियम कुशीनगर में आयोजित होगा। इसके बाद मंडलीय चयन ट्रायल 30 जून 2026 को प्रातः 10 बजे से सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम, गोरखपुर में कराया जाएगा। चयनित खिलाड़ी 10 से 12 जुलाई 2026 तक वाराणसी में आयोजित प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर महिला एवं पुरुष तैराकी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। प्रतियोगिता में प्रत्येक महिला एवं पुरुष खिलाड़ी अधिकतम पांच स्पर्धाओं में भाग ले सकेगा। इसमें 14 वर्ष या उससे अधिक आयु के तैराक प्रतिभाग करने के पात्र होंगे। वर्ष 2012 में जन्मे तैराक भी सीनियर वर्ग की जनपद एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकेंगे। प्रतियोगिता के अंतर्गत फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक, व्यक्तिगत मेडले, फ्री स्टाइल रिले, मेडले रिले, मिश्रित फ्री स्टाइल रिले तथा मिश्रित मेडले रिले स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। उप क्रीड़ा अधिकारी ने जनपद के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों से अपने संस्थानों के पात्र महिला एवं पुरुष तैराक खिलाड़ियों को समय से चयन ट्रायल में भेजने का अनुरोध किया है।

## जुलाई-सितंबर के लिए थाना समाधान दिवस का रोस्टर जारी, अधिकारियों को अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश

कुशीनगर। जनसमस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को आयोजित होने वाले थाना दिवस/समाधान दिवस के लिए जुलाई से सितंबर 2026 तक का रोस्टर जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुपालन में सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित तिथियों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि थाना समाधान दिवस का आयोजन प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक किया जाएगा। समाधान दिवस में थाना क्षेत्र के सभी राजस्व ग्रामों के राजस्व एवं चकबंदी विभाग के कर्मचारी, पुलिस विभाग के निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक, विकास विभाग, विद्युत विभाग तथा नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका एवं नगर पंचायत के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी निर्धारित समय तक थाना परिसर में पहुंचकर प्राप्त शिकायतों की सुनवाई एवं उनके निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित करें। शिकायतों की प्रकृति के अनुसार पुलिस, राजस्व अथवा संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की जाएगी तथा यथासंभव शिकायतों का निस्तारण उसी दिन मौके पर जाकर किया जाएगा। निस्तारित प्रकरणों की प्रविष्टि जीडी एवं समाधान दिवस रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन मामलों में स्थल निरीक्षण आवश्यक होगा, वहां पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम भेजी जाएगी। गंभीर मामलों में थानाध्यक्ष, तहसीलदार, उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी स्वयं मौके का निरीक्षण कर समस्या के समाधान की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता से संतुष्टि प्रमाणपत्र अथवा हस्ताक्षर प्राप्त कर उसका मोबाइल नंबर भी दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन शिकायतों का निस्तारण थाना समाधान दिवस में नहीं हो सकेगा, उन्हें आगामी तहसील दिवस में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक समय-समय पर किसी भी दो थानों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। वहीं अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) एवं अपर पुलिस अधीक्षक भी कम से कम दो थाना क्षेत्रों का निरीक्षण कर कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। पुलिस उपाधीक्षक अपने अधीनस्थ थानों का भ्रमण कर व्यवस्था की निगरानी करेंगे। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों तथा अवैध रूप से संचालित स्लाटर हाउस से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर पंजीकरण एवं निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जनपद के सभी राजस्व, पुलिस एवं चकबंदी अधिकारियों को रोस्टर के अनुसार नामित करते हुए शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

## सैनिक बंधु की बैठक में पूर्व सैनिकों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश

कुशीनगर।

जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सैनिक बंधु की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल डॉ. सुधाकर त्यागी, पूर्व सैनिक, वीर नारियां तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के प्रारंभ में जिलाधिकारी ने पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों का स्वागत करते हुए पिछली बैठक में उठाए गए मामलों की समीक्षा की। इसके बाद बैठक की कार्यवाही आगे बढ़ाई गई, जिसमें कुल 21 पूर्व सैनिक एवं विधवाएं शामिल रहीं। बैठक के दौरान पूर्व सैनिकों एवं एक सेवारत सैनिक की ओर से कुल चार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए। इनमें न्यायालय में लंबित वाद, भूमि पैमाइश तथा चकरोड निर्माण से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रहीं। जिलाधिकारी ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई कर समस्याओं के शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए।

बैठक में सूबेदार हर पिंन्द्र सिंह (एनसीसी बटालियन पडरौना), कैप्टन लाल बहादुर त्रिपाठी, कैप्टन शम्सुद्दीन अंसारी, कैप्टन दयाशंकर पाण्डेय, हवलदार शारदा प्रसाद तथा पीएलवी अमिताभ कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य पूर्व सैनिक एवं वीर नारियां उपस्थित रहीं। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की समस्याओं का समयबद्ध और संवेदनशील समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। उनके सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। बैठक में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के प्रभाकर नाथ तिवारी, राजेश कुमार गुप्ता, धर्मशीला, जालंधर प्रसाद सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे।

**ओबीसी विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका**

## भटनी में निःशुल्क ओ लेवल व सीसीसी कोर्स शुरू

भटनी देवरिया। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के विद्यार्थियों के लिए इन्फोटेक ऑफ कंप्यूटर साइंस, भटनी में निःशुल्क ओ लेवल एवं सीसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। संस्था द्वारा बताया गया कि प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद विद्यार्थियों के लिए शत-प्रतिशत प्लेसमेंट कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें। इच्छुक विद्यार्थी अपना नामांकन 5 जुलाई 2026 तक करा सकते हैं। नामांकन एवं अन्य जानकारी के लिए विद्यार्थी इन्फोटेक ऑफ कंप्यूटर साइंस, भटनी रेलवे स्टेशन के निकट, रामपुर खुरहुरिया स्थित संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नम्बर 8931039690 से संपर्क कर सकते है।

## घायल व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए

**जिलाधिकारी ने विगत माह में हुई सड़क दुर्घटनाओं तथा उनमें हुई मृत्यु के मामलों की जानकारी ली**

महराजगंज।

जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति, उनके कारणों, चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स की स्थिति तथा उन पर किए गए सुधारात्मक कार्यों सहित विभिन्न बिंदुओं की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने विगत माह में हुई सड़क दुर्घटनाओं तथा उनमें हुई मृत्यु के मामलों की जानकारी ली। यातायात निरीक्षक ने बताया कि मई 2026 में कुल सड़क दुर्घटनाएं 32 हुई हैं, जिनमें 26 मृत्यु हुई हैं और 08 घायल हुए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क दुर्घटना अत्यंत गंभीर विषय है और इनको रोकने के लिए सभी जरूरी उपाय सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित किया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस संदर्भ में उन्होंने महराजगंज-ठूठीबारी मार्ग पर सड़क निर्माण के दौरान सड़क सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर एनएच पीडब्ल्यूडी को कड़ी फटकार लगाते हुए सभी सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया कि सभी चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर शीघ्र सुधारात्मक कार्य सुनिश्चित किए जाएं। इन स्थलों पर साइन बोर्ड, रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप, स्पीड ब्रेकर, चेतावनी संकेतक एवं कैट लाइट अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, जिससे तीव्र मोड़ों एवं दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान आसानी से हो सके। साथ ही इनके आसपास अतिक्रमण को हटाने हेतु अभियान चलाएं। जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा को लेकर प्रवर्तन अभियान को प्रभावी ढंग से किए जाने का निर्देश दिया। एआरटीओ ने बताया कि इस माह 09 ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जिनसे सड़क दुर्घटना में कोई भी मौत हुई है और 22 लाइसेंस के निलंबन की संस्तुति भेजी गई है। जिलाधिकारी ने सड़क दुर्घटना में मौत रोकने हेतु फरेंदा में ट्रामा सेंटर की स्थापना हेतु प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने हेतु निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तत्काल इलाज बेहद अहम है। जिलाधिकारी ने स्कूल वाहनों के लिये फिटनेस प्रमाण पत्र की अनिवार्यता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। जिन वाहनों के पास फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं है, उनको सीज करें। साथ ही स्कूलों में व्यापक स्तर पर जागरूकता कैंप आयोजित किए जाने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया। हाईवे से जुड़े संपर्क मार्गों पर स्पीड ब्रेकर लगाने के निर्देश भी दिए, ताकि संपर्क मार्गों से आने वाले वाहनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में अधिशासी अभियंता राजकुमार मिश्रा, सहायक परिवहन अधिकारी मनोज सिंह, डीआईओएस प्रदीप शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

### ममता बनर्जी का बागी नेताओं को जवाब- फरहाद हकीम-अरूप बिस्वास समेत 8 को टीएमसी से किया आउट

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से ममता बनर्जी की पार्टी में बगावत का दौर जारी है। कई नेता ममता बनर्जी का साथ छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन इस बार ममता ने ही बागी नेताओं पर पलटवार किया है। ममता बनर्जी ने टीएमसी से पार्टी-विरोधी गतिविधियों के कारण फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास और छह अन्य नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट ने आज मंगलवार, 23 जून को उनके पूर्व सहयोगी और कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहाद हकीम और सात अन्य बागी विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। फिरहाद हकीम के अलावा, निकाले गए नेताओं में जावेद अहमद खान, अरूप रॉय, रथिन घोष, बिप्लब मित्रा, सबीना यास्मीन, अरूप बिस्वास और स्नेहाशीष चक्रवर्ती शामिल हैं। यह कार्रवाई बागी गुट के पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पार्टी की चेयरपर्सन पद से हटाने के एक दिन बाद की गई है। ममता के नेतृत्व वाले गुट ने पहले बागी नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया और इसके कुछ घंटों बाद इन नेताओं को पार्टी से निकाल दिया

## भरत भूषण मुठभेड़ मामले में बड़ा मोड़, डीएसपी और तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज





आरा। भोजपुर जिले के चर्चित भरत भूषण तिवारी मुठभेड़ मामले में नया मोड़ आ गया है। शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी की मौत के मामले में उनकी मां आशा देवी के बयान पर शाहपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दर्ज एफआईआर में जगदीशपुर के डीएसपी, शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत अन्य पुलिसकर्मियों को आरोपित बनाया गया है।

**मृतक की मां ने पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप**

आशा देवी ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि उनके पुत्र भरत भूषण तिवारी को पुलिस ने गोली मारकर हत्या की है। उन्होंने कहा कि घटना के दौरान भरत ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की और बाद में गोली चला दी, जिससे उनकी मौत हो गई।

**एसडीपीओ के आदेश पर मारी गई पांच गोलियां**

एफआईआर में गंभीर आरोप लगाया गया है कि जगदीशपुर डीएसपी के निर्देश पर पुलिसकर्मियों ने भरत भूषण तिवारी को पांच गोलियां मारीं। गोली लगने के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस उन्हें वाहन में बैठाकर अपने साथ ले गई। बाद में परिजनों को उनकी मौत की सूचना दी गई।

**पिता को भी पूरे दिन थाने में बैठाने का आरोप**

आशा देवी ने आवेदन में यह भी कहा है कि घटना के बाद उनके पति कामेश्वर तिवारी को थाने ले जाकर पूरे दिन बैठाए रखा गया। शाम में पुलिस की ओर से परिवार को सूचना दी गई कि भरत भूषण तिवारी की मौत हो चुकी है।

**एसपी बोले- आवेदन के आधार पर कराई जा रही जांच**

भोजपुर के एसपी राज ने कहा है कि प्राप्त आवेदन के आधार पर जांच कराई जा रही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब पूरे मामले की जांच पर सभी की नजरें टिकी हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मुठभेड़ की परिस्थितियां क्या थीं और लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है।

## आप विधायक चैतर वसावा समेत नौ दोषी करार, वन अधिकारियों से मारपीट में मिली सात साल की सजा



अहमदाबाद। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। नर्मदा जिले की एक अदालत ने पार्टी के विधायक चैतर वसावा, उनकी पत्नी और सात अन्य लोगों को वन विभाग के अधिकारियों से मारपीट, धमकी और वसूली के मामले में दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब चैतर वसावा दक्षिण गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में पार्टी के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक माने जाते हैं। अदालत के इस फैसले से राज्य में ,क की राजनीतिक रणनीति को बड़ा नुकसान माना जा रहा है। चैतर वसावा गुजरात ,क के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। वह 2022 के विधानसभा चुनाव में डेडियापाड़ा सीट से जीतकर चर्चा में आए थे। उनकी जीत ने दक्षिण गुजरात के आदिवासी इलाके में आप को मजबूत आधार दिया था। चैतर वसावा ने खुद को आदिवासी भूमि अधिकारों के प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया था। हालांकि, अब अदालत के फैसले ने उनकी राजनीतिक राह मुश्किल कर दी है। फिलहाल इस फैसले पर ,क की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह मामला 30 अक्टूबर 2023 का है। आरोप है कि वन विभाग के अधिकारियों ने जंगल की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए कुछ ग्रामीणों को निर्देश दिए थे। इसके बाद चैतर वसावा ने पांच वन अधिकारियों को अपने डेडियापाड़ा स्थित घर बुलाया। प्राथमिकी के मुताबिक, चैतर वसावा और उनके साथियों ने अधिकारियों के साथ अभद्रता की, एक अधिकारी के साथ मारपीट की और प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा देने की मांग की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, चैतर वसावा ने इस दौरान कथित तौर पर हवाई फायरिंग भी की थी। आरोप है कि जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया, उसके लिए उनके पास वैध लाइसेंस नहीं था। इसके चलते उन पर आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा दंगा, वसूली, सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी करने से रोकने और धमकी देने जैसी धाराएं भी लगाई गईं।

## लखनऊ अग्निकांड : 15 मौतों के लिए जिम्मेदार अफसरों का केवल सस्पेंशन नहीं, दर्ज हो एफआईआर, आप सांसद ने की मांग

लखनऊ । आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और सांसद संजय सिंह ने आज प्रेसवार्ता में प्रदेश और केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड और अयोध्या में प्रभु श्रीराम मंदिर निर्माण में हो रहे कथित भ्रष्टाचार व चोरी को लेकर डबल इंजन सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। संजय सिंह ने लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की दर्दनाक मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिस कंप्यूटर सेंटर की बिल्डिंग में आग लगी, उसे ध्वस्त करने का आदेश 2016 में ही हो चुका था। फिर यह अवैध और जर्जर बिल्डिंग कैसे खड़ी रही? किसके संरक्षण में इसे चलाया जा रहा था, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सांसद ने फायर डिपार्टमेंट की बदहाली पर कहा कि जब लोग दमकल विभाग को फोन कर रहे थे, तो समय पर कोई गाड़ी नहीं पहुंची। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हर अग्निकांड के बाद केवल जांच का नाटक होता है। 1. उत्तर प्रदेश के पूरे फायर डिपार्टमेंट की समीक्षा की जाए, विभाग का बजट बढ़ाया जाए और उन्हें आधुनिक उपकरण, पाइप व



गाड़ियाँ उपलब्ध कराई जाएं। दोषी अधिकारियों पर निलंबन (सस्पेंशन) जैसी रस्म अदायगी के बजाय सीधे एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए। 2. मृतकों के परिजनों को दिया जा रहा 2-2 लाख और 5-5 लाख रुपये का मुआवजा एक क्रूर मजाक है। अडानी जैसे मित्रों पर दौलत लुटाने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पीड़ितों को पर्याप्त सम्मानजनक मुआवजा दें।

3. संजय सिंह ने बताया कि उन्होंने इस हादसे में घायल हुई बेटी लवप्रीत से अस्पताल में मुलाकात की है, जिसने बताया कि आग नीचे से इतनी तेजी से फैली कि संभलने का मौका नहीं मिला। वहीं एक अन्य घायल बच्चा जयंत इस समय आईसीयू में भर्ती है। प्रेसवार्ता में संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट और भाजपा नेताओं पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, प्रभु श्रीराम के मंदिर में कोई सामान्य चोरी नहीं हुई है। चंपत राय और ट्रस्ट के लोगों ने यह चोरी सीधे तौर पर ईडी पार्टी यानी भाजपा के लिए की है। जमीनों की खरीद के लिए मोदी जी के प्रतिनिधि रहे ज्ञानेश कुमार के रहते हुए जमीनों के दाम कई गुना बढ़ाकर घोटाले किए गए। उन्होंने कहा कि मेरे मेल भेजने के बाद भी एसआईटी ने साक्ष्य देने का लिये समय नहीं दिया है।

## विपक्ष को कल जोर का झटका लगा और आगे भी लगेंगे - एकनाथ शिंदे

मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना (उबाठा) के लोकसभा सांसदों के टूटने के बाद विधानसभा में दिखी फूट को लेकर मंगलवार को मखौल उड़ाते हुए कहा कि विपक्षी सदस्य जोर का झटका लगने की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और उन्हें और भी झटके लगने वाले हैं। विधानसभा में आदित्य ठाकरे नीत शिवसेना (उबाठा) और अन्य विपक्षी दलों के विधायकों ने मंत्रियों द्वारा दूसरे विभागों से जुड़े सवालों का जवाब दिये जाने पर आपत्ति जताई और सदन से बहिर्गमन किया, जिसके बाद शिंदे की यह तीखी प्रतिक्रिया आई है। विपक्ष ने मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा कुछ विभागों की जिम्मेदारी कुछ मंत्रियों को सौंपने पर आपत्ति जताई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के सदस्य जयंत पाटिल ने विधानसभा अध्यक्ष से फैसला वापस लेने की मांग की, जबकि आदित्य ठाकरे ने कहा कि सदन में उठाए गए मुद्दों का जवाब केवल संबंधित विभाग के राज्य मंत्री ही दे सकते हैं। कांग्रेस के नितिन राउत (कांग्रेस) ने कहा कि ऐसी व्यवस्था पहले कभी नहीं देखी गई थी। शिंदे ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और वह कार्यवाही में रचनात्मक रूप से भाग लेने के बजाय उसमें बाधा डाल रहा है। उप मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष शिंदे ने कहा, सवालों के जवाब देने और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के लिए मंत्रियों को नियुक्त करने से यह सुनिश्चित हुआ कि सदस्यों को ज्यादा जानकारी मिले। सदन में मौजूद रहना और सदस्यों के सवालों का जवाब देना सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, मैं खुद सदन में आता हूं और मुख्यमंत्री भी खुद आकर जवाब देते हैं। इसलिए, यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। शिवसेना नेता ने विरोध कर रहे सदस्यों पर तंज कसते हुए कहा, जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे पूरा किया जाना चाहिए। आप बस कुछ भी बोलते नहीं रह सकते, बेकार की बातें करके सदन का समय बर्बाद नहीं कर सकते। विपक्षी खेमे की खाली कुर्सियों की ओर इशारा करते हुए शिंदे ने कहा कि उन्हें (विपक्ष को) पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने संभवतः शिवसेना (उबाठा) के छह बागी सांसदों के बुधवार को पाला बदलकर शिवसेना में शामिल होने का संदर्भ देते हुए कहा, कल उन्हें जोर का झटका लगा। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उन्हें आगे और भी झटके लगने वाले हैं।

## नीट विवाद पर धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा हमला, बोले- राहुल टुकड़े-टुकड़े ताकतों के साथ



नई दिल्ली । केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक विवाद के बीच नीट में बड़े बदलावों की योजना बताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अब तक का सबसे तीखा हमला किया है। इंटरव्यू में प्रधान ने कहा कि अगले साल से नीट के कंप्यूटर-बेस्ड फ़ॉर्मेट में बदलने की संभावना है।

उन्होंने पेपर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया और राहुल गांधी पर राजनीतिक फ़ायदे के लिए छात्रों के बीच डर फैलाने का आरोप लगाया। प्रधान ने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। लेकिन उन्हें छात्रों के मन में बेवजह डर पैदा नहीं करना चाहिए। उन्होंने परीक्षा सुधारों, छात्रों की चिंताओं और विरोध प्रदर्शनों पर भी बात की। जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे कुछ समूहों का जिक्र करते हुए प्रधान ने कहा, जो लोग देश को टुकड़े-टुकड़े करना चाहते हैं, वही लोग आज जंतर-मंतर पर ढोल बजा रहे हैं। (वही लोग जो देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, आज जंतर-मंतर पर ढोल बजा रहे हैं। क्या वहां कोई छात्र भी है?) कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कई दिनों और रातों से जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। मंत्री ने नागपुर के उस छात्र से जुड़े विवाद पर सबसे कड़ी आलोचना की, जिसका परीक्षा केंद्र अबू धाबी में आवंटित किया गया था। प्रधान ने दावा किया कि छात्र ने पोर्टल के जरिए खुद अबू धाबी को चुना था और यह पसंद कई बार रिकॉर्ड की गई थी। उन्होंने कहा कि बाद में एनटीए ने परिवार से संपर्क किया और छात्र को नागपुर से परीक्षा देने का मौका भी दिया। इसके बावजूद, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह सब साफ होने के बाद भी, राहुल गांधी ने इस मामले पर एक लंबा मैसेज पोस्ट किया। अगर राहुल गांधी में जरा भी नैतिकता और जवाबदेही बची है, तो उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रधान ने आगे आरोप लगाया कि गांधी किसी विवाद के शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह बस इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि नीट में कुछ गड़बड़ हो ताकि वह उस पर राजनीति शुरू कर सकें। उन्होंने कहा कि सारी हदें तब पार हो गईं जब कर्नाटक में उनकी अपनी पार्टी की एक राजनीतिक रैली ने हंगामा खड़ा कर दिया। फिर उनके कुछ नेताओं ने गैर-जिम्मेदाराना बयान देते हुए पूछा कि छात्र पहले क्यों नहीं निकले। यह बात उन्होंने 21 जून को हुई कांग्रेस की रैली के बारे में कही, जिस दिन नीट का री-टेस्ट था। प्रधान ने आगे कहा कि क्या आपमें इतनी समझ नहीं थी कि रैली कहीं और करते? क्या उसे वहीं करना बहुत जरूरी था? मंत्री ने गांधी पर संस्थानों और युवाओं, दोनों में भरोसा न करने का आरोप भी लगाया।

### मानसून 12 दिन लेट मुंबई पहुंचा, झमाझम बारिश जारी

नई दिल्ली । मानसून 12 दिन की देरी के बाद मंगलवार को मुंबई पहुंच गया है। आमतौर पर मानसून 11 जून तक मुंबई पहुंच जाता है। मानसून के पहुंचते ही शहर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण पश्चिम मानसून तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। अगले 2-3 दिनों में गुजरात और मध्य प्रदेश में पहुंच सकता है। इसके बाद 3-4 दिनों में उत्तर प्रदेश में भी एंट्री होगी। दिल्ली में मंगलवार दोपहर को धूल भरी आंधी चली। इससे कुछ देर के लिए दिन में ही अंधेरा छा गया। वहीं, मध्य प्रदेश के 17 जिलों में सोमवार को बारिश हुई। छतरपुर में बिजली गिरने से दो लड़कियां झुलस गईं। इनमें से एक की अस्पताल में मौत हो गई।

# रिपोर्ट में एफआईआर समेत कई बड़ी सिफारिशें एसआईटी ने चंपतराय को भी बनाया गबन का आरोपी

### राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला



**'20 पेज की जांच रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज कराने व ट्रस्ट के पुनर्गठन की सिफारिश**

**'वरिष्ठ अधिकारी को मंदिर का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने का सुझाव**

**'एसआईटी ने दिया सुझाव, पिछले पांच वर्षों के चढ़ावे का कराया जाए ऑडिट**

लखनऊ।

अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। मंगलवार को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को सौंपी गई 20 पन्नों की जांच रिपोर्ट में एसआईटी ने जिम्मेदारों पर सवाल उठाने के साथ ही एफआईआर दर्ज कराने, ट्रस्ट के पुनर्गठन और किसी वरिष्ठ अधिकारी को मंदिर का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करने की सिफारिश की है।

**एसआईटी ने रिपोर्ट में ये सब लिखा**

सूत्रों के अनुसार, अब तक की जांच में एसआईटी ने मंदिर में नकदी चोरी के अलावा भक्तों द्वारा दान किए गए कुछ आभूषणों के भी गायब होने को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है। रिपोर्ट में चढ़ावे की गणना से जुड़े कर्मचारियों की भर्ती, निगरानी व्यवस्था में खामियां, ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों, बैंक के कर्मचारियों व अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। पिछली सात जून को मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला चर्चा में आने के बाद 13 जून को सरकार ने ट्रस्ट के अनुरोध पर लखनऊ के मंडलायुक्त डॉ. विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने 15 जून से मामले की जांच शुरू की थी। सरकार ने एसआईटी को सात दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

**150 लोगों से पूछताछ की जानकारी**

एसआईटी ने फिलहाल अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र, मनीष यादव, राजेश पाठक, रमाशंकर, अविनाश शुक्ल, कृष्णदेव तिवारी, सुभाष श्रीवास्तव सहित ट्रस्ट व बैंक से जुड़े आरोपितों सहित 150 लोगों से पूछताछ की जानकारी रिपोर्ट में दी है। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी ने ट्रस्ट महासचिव चंपतराय, सदस्य डॉ. अनिल मिश्र, व्यवस्थापक गोपाल राव, व्यवस्था से जुड़े रामशंकर यादव टिंकू सहित कुल 14 लोगों को आरोपी बनाया है। जांच के दौरान दर्ज किए गए कई बयान ट्रस्ट के उपलब्ध अभिलेखों से मेल नहीं खा रहे हैं। ऐसे में एसआईटी मामले की जांच का दायरा और बढ़ सकती है। सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने पिछले पांच वर्षों के चढ़ावे का ऑडिट कराने का भी सुझाव दिया है। अब सरकार जल्द ही इस रिपोर्ट को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजेगी। इसके बाद गृह मंत्रालय यह तय करेगा कि ट्रस्ट में किन सदस्यों को हटाया जाए।

**अब तक दो करोड़ रुपये बरामद**

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पांच आरोपितों लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर उर्फ टिंकू की निशानदेही पर दो करोड़ रुपये बरामद किए जा चुके हैं। एक सप्ताह की जांच में कई प्रकार की खामियां मिली हैं और दानपात्रों की चाबी रामशंकर यादव टिंकू के पास पाई गईं। यह भी पता चला है कि सेवादारों को गबन की जानकारी पहले से थी। सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने मंदिर के प्रबंधन के लिए पेशेवर तरीका अपनाने, दान राशि की गणना का साप्ताहिक ऑडिट कराने, प्रतिदिन चढ़ावे में आने वाली राशि की इंट्री कराने, सीसीटीवी कैमरों का डाटा स्टोरेज 45 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने व आरोपितों को जांच पूरी होने तक अयोध्या न छोड़ने की सिफारिश की है। एसआईटी के अध्यक्ष ने कहा कि प्रारंभिक गोपनीय जांच रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव को सौंपी गई है। फिलहाल अभी तक की जांच में जो जानकारियां सामने आई हैं उसे रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है।

**रिपोर्ट में यह भी है खास**

जांच रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी से लेकर कमीशनखोरी तक के साक्ष्य जुट गए हैं। साथ ही मंदिर में कर्मचारियों की नियुक्ति व गणना प्रक्रिया में भी हेरफेर की आशंका जताई गई है। सूत्रों के अनुसार, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा व निर्माण सहायक गोपाल राव को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया गया है। वहीं, चढ़ावा चोरी में 25 से 30 लोगों की सीधी भूमिका सामने आ रही है। बिना तलाशी के मंदिर कर्मियों की आवाजाही पर भी सवाल उठाया गया है।

## ममता जो सीट हारीं, वहां ईवीएम-वीवीपैट सुरक्षित रखने का आदेश

**हाईकोर्ट बोला- जरूरत पड़ने पर जांच होगी; भवानीपुर में शुभेंदु 15,000 वोटों से जीते थे**

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट की मतगणना से जुड़े सभी अहम सबूत सुरक्षित रखने का आदेश दिया। अदालत ने रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर सुनवाई करते हुए कहा कि EVM, VVPAT, CCTV फुटेज और अन्य संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। जस्टिस गौरांग कांत ने मतगणना केंद्र बने शेखावाटी मेमोरियल स्कूल के अंदर और बाहर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, जरूरत पड़ने पर इन सभी साक्ष्यों की जांच होगी। अदालत की अनुमति के बिना इन्हें न तो मिटाया जाएगा, न बदला जाएगा, न नष्ट किया जाएगा और न ही इनके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की जाएगी। अदालत ने मामले में सभी संबंधित पक्षों को शामिल करने के आदेश दिए हैं। इसके तहत शुभेंदु अधिकारी, उनके सलाहकार सुब्रत गुप्ता और सुनील अग्रवाल को पक्षकार बनाया जाएगा। भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,105 वोटों से हराया था। ममता बनर्जी ने 16 जून को भवानीपुर सीट के चुनावी नतीजे को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

ममता खुद याचिका दाखिल करने हाईकोर्ट पहुंचीं और रिजल्ट की वैधता की जांच करने की मांग की। उन्होंने याचिका में कहा कि चुनाव गलत तरीके से हुआ है। 12 राउंड की काउंटिंग के बाद इलेक्शन एजेंट और मुझे पीटा गया और बाहर कर दिया गया। भवानीपुर सीट से ममता तीन बार विधायक रह चुकी हैं। चुनाव के दौरान उन्होंने मतगणना में गड़बड़ी और अपने साथ मारपीट के आरोप भी लगाए थे।

## 10 भारतीय जहाज अब भी फारस की खाड़ी में, विदेश मंत्रालय ने सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान को भी लताड़ा

नई दिल्ली । पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत ने मंगलवार को कई अहम जानकारियां साझा कीं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य से भारतीय जहाजों की आवाजाही जारी है और अब तक 11 भारत-गामी जहाज सुरक्षित तरीके से इस मार्ग से गुजर चुके हैं। वहीं, कतर के रास लाफान औद्योगिक शहर में हुए गैस संयंत्र विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि भी की गई है। इसके अलावा भारत-चीन संबंधों, ब्रिक्स देशों की सुरक्षा बैठक और पाकिस्तान के आरोपों पर भी सरकार ने अपना पक्ष रखा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नियमित प्रेस वार्ता में कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति पर भारत लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि फिलहाल फारस की खाड़ी क्षेत्र में भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज मौजूद हैं। इसके अलावा दो भारतीय जहाज हाल ही में फारस की खाड़ी में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे यह साफ है कि क्षेत्र में समुद्री यातायात पूरी तरह ठप नहीं हुआ है। मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि शेष भारतीय जहाज भी जल्द सुरक्षित तरीके से होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, 17 जून को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने के बाद से अब तक 11 भारत-गामी जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर चुके हैं। इनमें तीन भारतीय ध्वज वाले कच्चा तेल टैंकर शामिल हैं, जिनमें प्रत्येक में करीब 2.85 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल लदा हुआ है। इसके अलावा एक विदेशी ध्वज वाला एलपीजी वाहक, एक विदेशी ध्वज वाला कच्चा तेल टैंकर और छह विदेशी ध्वज वाले उर्वरक ढोने वाले मालवाहक जहाज भी शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के युद्ध वाले बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा कि पाकिस्तान इस तरह के बयान देकर अपनी नाकामियों और मानवाधिकार उल्लंघनों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत पाकिस्तान के इन मनगढ़ंत दावों को पूरी तरह खारिज करता है। दरअसल, ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में कहा था कि अगर पाकिस्तान की जल सुरक्षा को खतरा हुआ तो उनका देश भारत के खिलाफ युद्ध करने से भी पीछे नहीं हटेगा। यह बयान ऐसे समय आया है, जब भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का उसका फैसला फिलहाल अपरिवर्तित रहेगा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि वहां जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान की दशकों पुरानी आर्थिक शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन और प्रशासनिक दमन की नीतियों का परिणाम है। भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोकने, इंटरनेट बंद करने और निहत्थे नागरिकों पर बल प्रयोग जैसे कदम उठाए हैं। भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को उसके मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराने की भी अपील की। रणधीर जायसवाल ने कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी गैस सुविधा केंद्र में हुए विस्फोट को बेहद दुखद बताया।